

प्रेषक,

एस.के. मुद्दू,  
अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-1

देहरादून

दिनांक 13 सितम्बर 2010

**विषय:** चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में नागरिक अधिकार (संरक्षण) 1956 के क्रियान्वयन हेतु अनुदान संख्या-30 के आयोजनागत पक्ष के प्राविधानित धनराशियों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 187/XXVII(1) दिनांक 30 मार्च, 2010 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में समाज कल्याण विभाग में नागरिक अधिकार (संरक्षण) के क्रियान्वयन हेतु आयोजनागत पक्ष के अनुदान संख्या-30 में धनराशि रुपये 22,50,000/- (संयोजित रूप से बीस लाख पचास हजार मात्र) की प्राविधानित धनराशि में संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग के उक्त शासनादेश में उल्लेखित एवं निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. विभागाध्यक्षों तथा अन्य नियंत्रक अधिकारियों के निर्वर्तन पर जो धनराशि रखी गयी है वह उनमें से जनपद के आहरण-वितरण अधिकारियों को एक सप्ताह के अन्दर तत्काल अवमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
2. वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 186/XXVII(1)/2010 दिनांक 30 मार्च, 2010 में उल्लेखित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. आयोजनागत/आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित अन्य धनराशियों हेतु नियमानुसार मांग प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किया जा सके। यदि किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हो।
5. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
6. यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय-व्ययक 2010-11 में बजट प्राविधान से अधिक प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय-व्ययक प्राविधान की सीमा तक ही व्यय की जायेगी।
7. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत प्राविधानित या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त किया जाए।

8. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर स्याही से अनुदान संख्या-30 तथा आयोजनेत्तर/आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, शब्दों में महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
9. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर ले। धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की रिपोर्टें यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
10. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो नंग में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय-सारिणी के अनुसार समर्पण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
12. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
13. बी0एम0-13 पर संकलित मासिक व्यय की सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
14. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिष्ठान प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम) आय-व्यय के सम्बन्ध में नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
15. यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
16. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-30 के अंतर्गत संलग्न तालिका में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नाम से दर्ज जाएगा।
17. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 441(P)/XXVII-3/2010 दिनांक 07 सितम्बर 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(एस.के. मुद्दट)


अपर मुख्य सचिव एवं अयुक्त।



पृष्ठांकन संख्या:- 836/XVII-1/2010-10(39)/2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव-मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊ मण्डल उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
10. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी, नैनीताल।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
12. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून।
13. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,  
  
(धीरेन्द्र सिंह दत्ता)  
उप सचिव।

शासनादेश संख्या:- 36/XVII.-1/2010-10(39)/2009,

दिनांक 13 सितम्बर, 2010 का संलग्नक

अनुदान संख्या-30

आयोजनागत

मत देना

लेखाशीर्षक :

2225-01-800-08-00

मुख्य शीर्षक : 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

उप मुख्य शीर्षक : 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण।

लघु शीर्षक : 800- अन्य व्यय।


उप शीर्षक : 08- नागरिक अधिकार (संरक्षण) अधिनियम 1956 का क्रियान्वयन।

ब्यौरेवार शीर्षक : 00-

(धनराशि हजार रुपये में)

मानक मद	आवंटित धनराशि
20- सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	2150
42- अन्य व्यय	100
योग	2250

(रुपये बाईस लाख पचास मात्र)

  
(धीरेन्द्र सिंह दत्ताल)  
उप सचिव।